शोध मंथन Vol. XV No.I Jan.-Mar.2024 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Impact Factor 8.870 (SJIF)

भारतीय अर्थव्यवस्था पर विमुद्रीकरण के प्रभाव का मूल्यांकन

डा० मधु शर्मा
अध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग
आर०एस०एस० पी०जी० कॉलेज, पिलखुवा, हापुड़
ईमेलः *dr.madhusharma2@gmail.com*

प्राप्तिः 10.03.2024
स्वीकृतः 17.03.2024

1

सारांश

विमुद्रीकरण एक मौद्रिक घटना है। जिसमें कि पूर्व में प्रचलित करेन्सी नोट की प्रचलन में वैद्यता समाप्त कर दी जाती है। सरकार के इस एक निर्णय से एक साथ काले धन, भ्रष्टाचार, जालीमुद्रा प्रचलन, आतंक का वित्त–पोषण आदि को नियंत्रित करने में अर्थव्यवस्था को मदद मिलती है। विमुद्रीकरण अच्छा कदम है किन्तु सावधानी व तैयारी के साथ। यही कारण है कि विश्व मे विमुद्रीकरण के परिणाम मिले जुले देखने में आये हैं, यदि बिना पूर्व तैयारी के विमुद्रीकरण कर दिया जाये तो परिणाम अति भयावह भी हो जाते है। म्यामार में सन 1987 मे विमुद्रीकरण किया गया किन्तु दिशाहीन होने के करण यहां 1000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गयी। उत्तर कोरिया में 2010 मे विमुद्रीकरण की असफलता से नाराज होकर वहां के शासक किमजोंग ने अपने वित्तमंत्री को फांसी पर लटका दिया। इसके वावजूद भी हम विमुद्रीकरण की विषेशताओं के कारण इसके प्रयोग को छोड़ नही सकते। यही कारण था कि आचार्य चाण्क्य व डॉ० भीमराव अम्बेडकर ने सुझाव दिया कि विमुद्रीकरण को प्रत्येक 10 वर्षों मे होते रहना चाहिये।

मुख्य बिन्दु

विमुद्रीकरण, भारतीय अर्थव्यवस्था, भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता।

प्रस्तावना

भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। वर्ष 2018–19 तक भारतीय अर्थव्यवस्था जीडीपी द्वारा मापी जाने वाली दुनिया की सातवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी लेकिन विश्व आर्थिक लीग की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, भारत 2019 में दुनिया की 5 वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए फ्रांस और ब्रिटेन दोनों देशों से आगे निकलते हुए 2019–20 में भारतीय अर्थव्यवस्था जीडीपी द्वारा मापी जाने वाली दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गयी है और अमेरिका और चीन के बाद भारत क्रय शक्ति समता में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वर्ष 1991 में तत्कालीन सरकार के नेतृत्व में एलपीजी (उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण) नीति को अपनाया गया जिसमें भारत की बंद अर्थव्यवस्था को वैश्विक व्यापार के लिए खुली अर्थव्यवथा का रूप दिया गया जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर बन सके। फिच रेटिंग एजेंसी के अनुसार, भारत का सकल घरेलू उत्पाद वित्त वर्ष 2012–13 में 5ण्5ः से निरंतर वृद्धि करते हुए वित्त वर्ष

2016–17 में 8ण्2ः की वृद्धि तक पहुंच गया जो कि संरचनात्मक सुधारों, उच्चतर प्रयोज्य आय के क्रमिक कार्यान्वयन द्वारा संचालित है परन्तु धीरे–धीरे वित्त वर्ष 2018–19 तक सकल घरेलू उत्पाद में कमी देखी गयी।

भारतीय अर्थव्यवस्था से काले धन (कर चोरी संबन्धी आय) को निश्क्रिय करने हेतु विमुद्रीकरण के प्रभाव का मूल्यंकन करना इस शोध पत्र का प्रमुख उद्देश है। विमुद्रीकरण एक ऐसा अस्त्र है जिससे कि एक साथ कई जटिल समस्याओं के समाधान प्रप्त हो जाते हैं। जाली मुद्रा को चलन से बाहर निकालना हो या भ्रष्टाचार पर रोक लगानी हो, आतंक का वित्तपोषण रोकना हो या कालेधन पर कार्यवाही कर इसे निष्क्रिय करना हो या आर्थिक स्थिरता लानी हो अथवा नई मुद्रा में समरूपता लानी हो जैसे बड़े कार्य विमुद्रीकरण से ही सम्भव हैं। इसका सफल प्रयोग अमेरिका व आर्टेलिया मे किया गया जबकि 1971 में ब्रिटेन मे, 1982 मे घाना में, 1984 में उत्तर कोरिया में, 1987 में म्यामार में, 1990 में जायरे में, 1991 में सोवियत रूस में, 2015 में पाकिस्तान में इसका प्रयोग असफल रहा। भारतीय अर्थव्यवस्था के तीन प्रमुख क्षेत्र हैं जिनका सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदन है। अर्थव्यवस्था के ये तीन क्षेत्र हैं कृषि अथवा प्राथमिक क्षेत्र, उद्योग अथवा द्वितीयक क्षेत्र और सेवा अथवा तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र का सीधा संबंध देश के प्राकृतिक संसाधनों से है जिसमें कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, पशु पालन और खनन क्षेत्र आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है और कच्चे माल के उपयोग से बुनियादी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। इसलिए, यह कहा जा सकता है कि प्राथमिक क्षेत्र एक बुनियादी क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, जो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के विकास में सहायता प्रदान करता है। द्वितीयक क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं, जो निर्माण गतिविधियों और तैयार माल व मूर्त उत्पादों के निर्माण में लगे हुए हैं। द्वितीयक क्षेत्र राष्ट्र के संभावित उपभोक्ताओं के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तृतीयक क्षेत्र प्रकृति में अमूर्त होते है, जो सेवा क्षेत्र पर केंद्रित है। इस क्षेत्र में उपभोक्ताओं द्वारा आवश्यक शिक्षा, चिकित्सा, होटल और वित्त जैसी सेवाओं का प्रावधान है। प्रारंभिक सभ्यता की शुरुआत प्राथमिक क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता के साथ हुई। हालांकि, खाद्य उत्पादन में अत्यधिक मांग के साथ, लोगों ने उद्योगों की ओर रुख करना शुरू कर दिया। यह 19 वीं शताब्दी के दौरान औद्योगिक क्रांति का कारण बना। इस तीव्र औद्योगिकीकरण ने अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र को जन्म दिया। इस प्रकार, अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र से तृतीयक क्षेत्र तक धीरे–धीरे चरणों में विकसित हुई।

"जब किसी देश में काले धन की एक सामानांतर अर्थव्यवस्था उत्त्पन्न हो जाती है और अर्थव्यवस्था में जाली मुद्रा हद से अधिक बढ़ जाती है तब सरकार द्वारा नोटबंदी अर्थात विमुद्रीकरण (क्मउवदमजपेंजपवद) किया जाता है, जिसके अन्तर्गत पुरानी मुद्रा को कानूनी तौर पर बंद कर नई मुद्रा जारी की जाती है।'' विमुद्रीकरण के बाद उस मुद्रा की कीमत शून्य हो जाती है, जिससे उस मुद्रा द्वारा किसी भी प्रकार का लेन–देन या विनिमय संभव नहीं हो पाता है । अर्थात मौजूदा मुद्राओं के उन्मूलन या पुरानी मुद्राओं को नए मुद्रा के साथ प्रतिस्थापित करने की प्रक्रिया को विमुद्रीकरण के रूप में जाना जाता है।

विमुद्रीकरण निश्चित रूप से ऐसी विधि है जो तत्काल काले धन को समाप्त कर देती है। तथा देश की समस्त मुद्रा प्रचलन में बाहर आ जाती है। विमुद्रीकरण एक रचनात्मक विध्वंश है भारत जैसे लोकतान्त्रिक देश में समान न्याय व आय असमानता जैसी समस्याओं के निराकरण हेतु आवश्यक हो जाता है, क्योकि लोकतंत्र में सभी को बढ़ने का समान अवसर प्राप्त होता है। आर्थिक असमानता जो कालेधन, भ्रष्टाचार, जाली नोटों आदि से उत्पन्न होती है, पर नियंत्रण आवश्यक है। इसी कारण भारत में अब तक तीन बार विमुद्रीकरण किया जा चुका है। प्रथम विमुद्रीकरण सन 1946 में तत्कालीन गवर्नर सर चिन्तामन देशमुख द्वारा घोषित किया गया। घोषणा करते हुए उन्होने कहा था कि हमारी अर्थव्यवस्था में कुछ मुद्रा अवैधानिक रूप से प्रवेश कर गयी है जोकि अर्थव्यवस्था को क्षति पहुचा रही है। इसलिये बड़े नोटों (10000, 5000, 1000) का विमुद्रीकरण आवश्यक है। इससे थोड़े समय के लिये कृषि को आर्थिक हानि अवश्य होगी किन्तु उसके बाद कृषि में बम्पर वृद्धि देखने को मिलेगी। साठ के दशक में के०एन० वाचू की अध्यक्षता में कालेधन पर एक जांच दल गठित किया गया था जिसने रिर्पोट मे काले धन पर अंकुश लगाने का सुझाव दिया। कम्युनिश्ट नेता ज्योतिर्मय बसु ने 4 दिसंबर 1972 को संसद में काग्रेस सरकार से यह प्रश्न किया कि सरकार काले धन पर कब कदम उठायेगी। तब भी तत्कालीन सरकार ने इस पर कोई प्रभावी कदम नही उठाया। दूसरा विमुद्रीकरण 1978 में जनतापार्टी की सरकार के समय गवर्नर आई०जी० पटेल द्वारा घोषित किया गया, और पुनः (10000, 5000, 1000) के नोटों को बन्द कर दिया गया क्योकि 1946 के विमुद्रीकरण के पश्चात 1954 को काग्रेस सरकार द्वारा उक्त नोटो पुनः प्रचलन में ले आये गये थे व इनका प्रभाव अर्थव्यवस्था पर बुरा पड़ रहा था।

तृतीय विमुद्रीकरण 08 नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 1000 व 500 के नोटो की वैधानिकता समाप्त करके किया गया। प्रसार भारती के अध्यक्ष ए० सूर्यप्रकाश ने अपने लेख में बताया कि वास्तव में यह विमुद्रीकरण अर्थव्यवस्था के लिये आवश्यक हो गया था। क्योंकि सन 2004 से बड़े वर्ग के नोटों की हिस्सेदारी तीव्रता से बढ़ने लगी थी। बड़े वर्ग के नोटों की हिस्सेदारी 34 फीसदी से बढकर मात्र 6 वर्षों की अल्पावधि मे (2010) तक बढ़कर 79 फीसदी हो गयी थी जबकि 2016 को इनकी हिस्सेदारी 87 फीसदी हो गयी थी। इस प्रकार 2004 से 2013 के दौरान बड़े वर्ग के नोटों की हिस्सेदारी में औसत वृद्धि 51 से 63 फीसदी के बीच रही। रिजर्व बैंक के अनुसार 1000 के रूपये के दो तिहाई नोट व 500 के नोट के एक तिहाई नोट जो कि मिलकर कुल छैः लाख करोड़ होते हैं जारी होकर कभी बैंक तक वापस आये ही नहीं। बैंक निगरानी से दूर ये नोट सोने और जमीन की कीमतें बढ़ा रहे थे, इन पर अंकुश लगाना आवश्यक हो गया था।

भारत में अनेक सर्वेक्षणों से यह स्पष्ट हो चुका है कि भारत में बड़ी मात्रा मे कालाधन एकत्रित हो चुका था 2004 से 2014 की अवधि मे हुए अनेको भ्रष्टाचार इसका प्रमाण प्रस्तुत करते है इन्ही घोटालों के कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ गयी परिणाम स्वरूप सोने व जमीन के मूल्यों मे बेतहाशा वृद्धि देखने को मिली। अर्थव्यवस्था की बनावटी तीव्र वृद्धि दर उक्त कृत्य का ही परिणाम थी किन्तु आवाम को इस भ्रम में रखा गया कि भारत तीव्र वृद्धि कर रहा है। 2014 में सत्ता परिवर्तन के प

चात कालेधन का मुद्दा गति पकड़ने लगा। ऐसे में कई परतें खुलने लगी और वास्तविक स्थिति सामने आने लगी।

भारतीय अर्थव्यवस्था में कई समस्याएं व्याप्त हैं। उदाहरण के लिए, कम पूंजी निर्माण, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सबसे महत्वपूर्ण काला धन। इसके अलावा, और भी कई समस्याएं हैं जो भारत कई वर्षों से भुगत रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कई प्रयासों के बाद भी हमें समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा है। भ्रष्टाचार देश की सबसे बड़ी समस्या है जो देश की लगभग सभी समस्याओं को प्रभावित करती है। यदि भ्रष्टाचार के कारणों का गहन अध्ययन किया जाए तो, तो हम यह पाते हैं कि नकद लेनदेन भ्रष्टाचार का मुख्य कारण है । नकद लेन–देन के कारण, लोगों को आसानी से धन का हस्तांतरण हो रहा है। भ्रष्टाचार के कारण सरकार ने जो भी प्रयास किए, वे लागू नहीं हो पाए हैं । उदाहरण के लिए, आजादी के बाद से, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने की कोशिश की गयी, लेकिन हमें सफलता नहीं मिली क्योंकि जो भी ध नराशि कृषि क्षेत्र के लिए आवंटित की जाती है, वह धनराशि जरूरतमंद व्यक्ति के हाथ में नहीं पहुंचता। हम अपने देश से भ्रष्टाचार और काले धन की समस्या का समाधान कर सकते हैं, उसके लिए काले धन के स्रोत को सबसे पहले खत्म करना होगाद्य देश में काले धन की बढ़ती दर का मूल कारण अपराधियों के लिए सख्त सजा का अभाव है। अपराधी अपनी भ्रष्ट गतिविधियों को छिपाने के लिए कर अधिकारियों को रिश्वत देते हैं।

वास्तव में काले धन का बढ़ना व उस पर नियन्त्रण करना दोनो ही अत्यन्त जटिल कार्य हैं। जे०एन०यू० के प्रो० अरूण कुमार ने अपनी चर्चित पुस्तक द ब्लेक मनी इन इन्डिया में कालेधन की समस्या को विस्तार से बताया है, आजादी के बाद सबसे पहले 1955–56 में ब्रिटेन के प्रो० एन० कालडोर ने सर्वप्रथम भारत में कालेधन पर प्रकाश डाला था उनका आकलन था कि भारत मे कालाध न जी०डी०पी० का 4 से 5 फीसदी तक है। तब से इसमें लगातार वृद्धि हो रही है।1995–96 में यह जी०डी०पी० का 40 प्रतिशत था और 2005–06 तक यह बढ़कर तकरीबन 50 प्रतिशत हो गया था। इस प्रकार कालेधन का अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था में समानान्तर अर्थव्यवस्था का रूप ले रहा है। प्रत्येक वर्ष लगभग 35 लाख करोड़ की ब्लेक इकोनोमी तैयार हो जाती है और इस राशि का तकरीबन 10 प्रतिशत विदेशों में चला जाता है। जो 2005–06 में बढ़कर 90 लाख करोड़ तक पहुंच गयी। यह कालाधन 77 टैक्स हैवन देशों में (स्विटजरलैंड, मारीशस, हांगकांग, बहमास, अर्जेंटीना, ब्रिटिशवर्जिन आदि मे) जमा है। जोकि कानूनी व गैरकानूनी दोनो प्रकार की गतिविधियो से पैदा हो रहा है। इस प्रकार की व्यवस्था वास्तव में भारत को बेरोजगार व गरीब देश बनाये हुये है।

भारतीय गरीब हैं लेकिन भारत देश गरीब नही रहा। ये कहना है स्विस बैंक के डायरेक्टर का, उनके अनुसार भारत का लगभग 280 लाख करोड़ रूपया इनके स्विस बैंक में जमा है। ये रकम इतनी बड़ी है कि भारत का आने वाले 30 वर्षों का बजट बिना करारोपण के ही बनाया जा सकता है। या यू कहें कि 60 करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर दिये जा सकते हैं। हर भारतीय को 2000 रूपये प्रतिमाह दिये जाये तो 60 वर्षों तक खत्म न हों। लगभग 15 लाख रूपये प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से

में आते हैं अर्थात भारत को ऋण लेने के लिये किसी विश्व बैंक की आवश्यकता नही पड़ेगी। जरा सोचिये हमारे भ्रष्ट राजनेताओं और नौकरशाहों ने किस प्रकार से देश को लूटा है, लूट का ये आंकड़ा 2011 तक का है। इस सिलसिले को रोकना अब बहुत आवश्यक हो गया है। अग्रेजों ने भारत पर 200 वर्ष शासन करके एक लाख करोड़ रूपये लूटे थे किन्तु आजादी के बाद केवल 64 वर्षों में ही हमारे भृष्टाचारियों ने 280 लाख करोड़ लूटे है, अर्थात प्रतिवर्ष लगभग 4.37 लाख करोड़ रूपये। 1978 में मोरार जी देसाई ने कहा था कि जब कालाधन बढ जाता है तो अर्थव्यवस्था के लिये खतरा बन जाता है विमुद्रीकरण की इस विधि के द्वारा जिनके पास काला धन होता है वह इसके बदले में लेने का साहस नहीं जुटा पाता है और काला धन स्वतरू ही समाप्त हो जाता है। आन्तरिक काला धन प्रायः नकदी में, स्वर्ण में व सम्पत्ति के रूप में रखा होता है। ऐसे में विमुद्रीकरण होते ही नकदी मूल्यहीन हो जाती है। हॉ कालेधन को पूर्णतः समाप्त करने के लिये चरण बद्ध रूप से कुछ और भी प्रयास करने की आवश्यकता होगी। एन०सी०ए०ई०आर० के कार्यक्रम में बोलते हुए पूर्व गर्वनर विमल जलान ने नोटबन्दी को सैद्धान्तिक रूप से ठीक लेकिन नतीजों के हिसाब से यह अच्छा साबित नही हुआ। पूर्व गवर्नर डी० सुब्बाराव ने नोटबन्दी को रचनात्मक विध्वंश का नाम दिया। उन्होने इसकी तुलना 1991 के आर्थिक सुधारों से की उन्होने कहा कि 1991 के बाद से अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर पैदा करने वाला नीतिगत नवप्रवर्तन है। इससे कालेधन को नष्ट करने में मदद मिली है। सुप्रीमकोर्ट द्वारा कालेधन पर गठित विषेश जांच दल के डिप्टी चेयरमैन उर्जित पसायत ने कहा कि अबतक 70,000 करोड़ रूपये के काला धन का पता चला है। कालेधन पर अपनी आठवी रिर्पोट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जानी है। तत्पश्चात सुप्रीम कोर्ट विमुद्रीकरण पर अपना निर्णय दे सके गा कि विमुद्रीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पडा है। अभी तक न्यायालय का जो भी रूख रहा है वह सकारात्मक ही देखने में मिला है।

भारत सरकार द्वारा संचालित 'स्वच्छता अभियान' के साथ–साथ, 'विमुद्रीकरण' को हमारे देश के इतिहास में काले धन के खिलाफ सबसे बड़ी उल्लेखनीय स्वच्छता अभियान के रूप में जाना जाता है। यहां तक कि अगर हम अपने देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं के बारे में बात करते हैं, तो हमारे देश के उत्थान में मुख्य दोष काले धन का अत्यधिक प्रसार है, जिसने हमारे देश की सार्वजनिक नीतियों और संस्थानों पर दुर्बल प्रभाव डाला है। देश में काला धन और जाली मुद्रा से आतंकवाद, अपराध और भ्रष्टाचार में वृद्धि होती है। कई समाधान निकाले जा रहे हैं लेकिन काले धन का मुकाबला करने का सबसे अच्छा समाधान डिजिटल लेनदेन या कैशलेस लेनदेन है क्योंकि इससे मुद्रा की अधिक भौतिक उपस्थिति छिपाने की संभावना कम हो जाती है। क्रेडिटध्डेबिट मनी, मनी वॉलेट, चेक आदि कैशलेस लेनदेन के विभिन्न तरीके हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि भारत एक विविध देश है, जिसमें विभिन्न रिवाजों और धर्मों के लोग रहते हैं, इसलिए लोगों को कैशलेस लेनदेन के उपयोग के बारे में साक्षर करने में कुछ समय लगेगा। कैशलेस होने के बाद, अर्थव्यवस्था से काला धन और भ्रष्टाचार भी अपने आप कम हो जाएगा। भारत में काला धन काले बाजार पर अर्जित धन है, जिस पर आय और अन्य करों का भुगतान नहीं किया गया है ।

वास्तव में विमुद्रीकरण का परिणाम निकलने लगे है चाहे पोंजी केपिटल हो या चिटफंड कम्पनियों इनका बन्द होना पकड़ा जाना, छोटे निवेशकों के रूपयों के वापसी की बात हो इन पहलुओं पर नोटबन्दी का प्रभाव देखने को तो मिल रहा है। किन्तु कोरोना के दुष्प्रभावों के वजह से विमुद्रीकरण के जो प्रभाव आपेक्षित थे उनका विष्लेषण किया जा पाना अब सम्भव नहीं है। हॉ विमुद्रीकरण से कालेधन को बाहर निकालने में सफलता प्राप्त अवश्य हुई है। फरवरी 2019 में तत्कालीन वित्तमंत्री पियूश गोयल ने संसद में बताया कि विमुद्रीकरण से सभी प्रकार के कालेधन को समाप्त करने के लिये उठाये गये विभिन्न उपायों के द्वारा 1.3 लाख करोड, रूपये का काला धन बरामद किया गया। जबकि सरकार ने विमुद्रीकरण के पूर्व 3 से 4 लाख करोड. रूपये बरामद करने की बात कही थी। नकली नोटों के प्रचलन को समाप्त करना सरकार द्वारा लागू किये गये विमुद्रीकरणका दूसरा सबसे बड, लक्ष्य था अतरू आंकडों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि विमुद्रीकरण की कार्यवाही से कालेधन को मात देने में सफलता तो प्राप्त हुई है हों यह अपेक्षित सफलता से कम है। जैसा कि विष्लेशण में बताया गया है कि अभी साठ लाख खाते ऐसे हैं जिनमें बड़ी मात्रा में नकदी जमा हुई है। इन खातों की जांच अभी प्रक्रियाधीन है। जॉच के बाद ही स्पश्ट हो पायेगा कि उक्त नकदी में कितना हेरफेर किया गया है अर्थत इसमें ब्लेक को व्हाइट बनाने का प्रयास है या वास्तव में यह मुद्रा व्हाइट ही है।

निष्कर्ष

जब बैंकों के माध्यम से पैसों का लेन–देन होता है तो काले धन के उत्पन्न होने की संभावना कम हो जाती है । जब धन का प्रवाह बैंक से बैंक तक होता है तब बैंकों को रिकॉर्ड मिल जाते हैं और यह पता लगाने योग्य भी हो जाता है कि अर्थव्यवस्था में कितनी मात्रा में काला धन है। अगर हम देखें तो सरकार द्वारा यह निर्णय सही सोचकर लिया गया था कि इस कदम से काले ध न पर नकेल कसी जा सकती है। हालांकि, ऐसा नहीं हुआ लोग अपने काले धन को नई मुद्रा में बदलने में सफल रहे। इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ ही काले धन का हिस्सा पकड़ा गया लेकिन यह काले धन के प्रतिशत में बहुत ही कम है। RBI की रिपोर्ट (2017–18) के अनुसार बैंक में 99.3 प्रतिशत पैसा वापस आ गया है। इसलिए विमुद्रीकरण ने काले धन को हटाने के अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सका । हालांकि, कुछ समय के लिए यह अवैध लेनदेन को रोक दिया था। फिर भी, लोग भ्रष्ट अधिकारियों की मदद से अपने पुराने नोटों को नए नोटों में बदलने में सक्षम थे। इसके अलावा, अधिकांश लोग काली मुद्रा को सोने और अन्य कीमती पत्थर में परिवर्तित कर रहे थे। काले धन का एक और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो लोग अपनी काली मुद्रा को विदेशी मुद्रा में रखते हैं, उन पर किसी भी प्रकार से विमुद्रीकरण का प्रभाव नहीं पड़ा। इसके अलावा, जो लोग अपनी काली मुद्रा को संपत्ति में रखते हैं, उन लोगों को भी विमुद्रीकरण के कारण प्रभावित नहीं किया सका है । इसलिए, यह निष्कर्ष निकलता है कि विमुद्रीकरण काले धन को कम करने में विफल रहा है । यदि सरकार ने 2000 रुपये और 500 रुपये के नए करेंसी नोट जारी नहीं किए होते सिर्फ विमुद्रिकृत नोटों के मूल्य के बराबर अन्य मूल्यवर्ग के नोटों में ही वृद्धि कर देते तो, उस स्थिति में लोगों के पास अपना पैसा बैंकों में जमा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता । उस समय विमुद्रीकरण कुछ हद तक और अधिक सफल हो सकता था। इसके अलावा विमुद्रीकरण के कारण कुछ हद तक नकली मुद्रा

पर नियंत्रण मिला। भारत सरकार ने नकली मुद्रा की समस्या को भारतीय अर्थव्यवस्था में हल करने में सक्षम बनाया। न केवल भारत में बल्कि कई अन्य देश भी जैसे पाकिस्तान, नेपाल और चीन जैसे देष जो भारतीय मुद्रा को प्रिंट करने के लिए नकली मुद्रा का उपयोग करते हैं, वह विमुद्रीकरण के कारण बंद हो गये।

संदर्भ

1. Aggarwal, N., Narayanan, S. (2017). Impact of India's Demonetization on Domestic Agricultural Markets. *SSRN Electronic Journal*.
2. Ashwani., Nataraj, G. (2018). Demonetisation in India: An Impact Assessment. *Journal of Business Thought*. 9(3). Pg. **11–23.**
3. Basu, A. (2018). Demonetisation and the Retail Market Perceptions: A Survey of the Vegetable Vendors in Siliguri. Business Spectrum. ISSN 2249-48048(1). Pg. **1–9.**
4. Bhattacharyya, R., Mehta, S.N. (2016). Demonetisation – Worst Effected the Small Traders, International Journal of Latest Technology in Engineering. *Management & Applied Science*. 5(12). Pg. **52–58.**
5. David, E.T., Emmanuela, A.O., Scholastica, E.U. (2018). Effect of Small and Medium Enterprises on Employment Generation in Nigeria. *International Journal of Trend in Scientific Research and Development*. Volume-2. Issue-4. Pg. **1544–1552.**
6. Deodhar, R.P. (2017). Black Money and Demonetisation. *SSRN Electronic Journal.*
7. Gaur, A.D., Padiya, J. (2017). From Demonetisation to Digitization of Indian Economy: The Road Ahead. Proceedings of International Conference on Strategies in Volatile and Uncertain Environment for Emerging Markets Indian Institute of Technology Delhi. (8). Pg. **598–607.**
8. Giri, P., Singh, Y. (2017). Demonetisation: An Analysis of Intended Benefits and Unintended Consequences. 6(7). Pg. **37–41. 227.**
9. Jose Hurtado Briceno, A., Zerpa de Hurtado, S. (2019). India-Venezuela: Analysis of Demonetization Measures. *International Journal of Advances in Management.*
10. Kataria, C.D., Hooda, M.J. (2015). *International Research Journal of Commerce, Arts and Science*. 6(4). Pg. **166–178.**
11. *National Monthly Refereed Journal of Research in Commerce & Management*. 4(4). Pg. **34–40.**